


20/10/15. | वकील काशीजी उपस्थित। कोर्टा ठाळा रू प्रि (का.)
जकार खुले न्यायालय हुकाम गय। कजनी प्रि (का.)
हुकार होकर इखिल इफतार हो।


सहायक कलेक्टर
SDO, मुझामाजारी

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री नाथूसिंह राठौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 215/2015

प्रार्थनी

1. मंगुदेवी पुत्री बनाराम पत्नी रूगनाथराम जाति मेघवाल निवासी सड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सावला पुत्र अमरा
2. राणा पुत्र हेमाराम
3. चेलाराम पुत्र हेमाराम
4. तिलोकाराम पुत्र हेमाराम
5. मंगलाराम पुत्र हेमाराम
6. समदादेवी पत्नी हेमाराम जातियान मेगवाल, निवासीयान सड़ा, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
7. माधाराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेगवाल, निवासी सड़ा, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार सिणधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने बाबत

उपस्थित :

1. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता प्रार्थनी

--: आदेश :-

दिनांक :- 20.10.2015

प्रस्तुत प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थनी ने यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थनी व विप्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 334, 360 कुल रकबा 59.18 बीघा मौजा सड़ा, खसरा संख्या 318 रकबा 99.02 बीघा माजा हरनिगर व खसरा संख्या 519 रकबा 51.05 बीघा मौजा सड़ा में आया हुआ है। उक्त भूमि में प्रार्थनी का 1/5 हिस्सा उनके पिता स्व. बनाराम के देहान्त होने पर उनके प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से प्राप्त हुई। प्रार्थनी के पिता के देहान्त पर उत्तराधिकार का नामान्तरण संख्या 147 विप्रार्थी संख्या 01 व विप्रार्थी 2 से 5 के पिता अमरा व हेमा ने पटवारी से मिलकर उनकी जाईन्दा बहनों को वारीसान न बताकर गलत व अवैध रूप से अपने नाम से तस्दीक करवाया। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थनी व विप्रार्थीगण अपने हिस्सेनुसार कब्जा व काश्त है। प्रार्थनी अनपढ व औरत जात होने के कारण इतने दिनों तक उन्हें अपना नाम खातेदारी में दर्ज होने का ज्ञान नहीं रहा और न ही विप्रार्थीगण ने प्रार्थनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी की। आज से करीबन सप्ताह भर पूर्व विप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने अपने नाम से प्रविष्टि का अनुचित लाभ उठाते हुए वाद ग्रस्त आराजी में से कुछ भूमि का बेचान करने पर उतारू है और कुछ भूमि का बेचान कर चुका है तथा प्रार्थनी के हक हिस्से की भूमि का भी बेचान कर प्रार्थनी को बेदखल करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थनी ने अपने हकों की घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद पेश किया गया।



सहायक कलेक्टर
SDO, गुडामालानी

प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2015 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थनी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने दावा उक्त वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थनी की पैतृक भूमि है, तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थी का है, जिससे प्रार्थनी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है और अगर निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अब इस न्यायालय को तय यह करना है कि क्या प्रार्थनी उक्त वादग्रस्त आराजी में विरुद्ध विप्रार्थीगण निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। पत्रावली के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रार्थनी स्व0 बनाजी की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक होने से उक्त विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थनी का हक निहित है। विप्रार्थीगण द्वारा बाबजूद नोटिस तामील प्रार्थनी के प्रार्थना पत्र का कोई विरोध नहीं किया है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थनी के हक में है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थनी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थनी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विरुद्ध विप्रार्थीगण दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 334, 360 कुल रकबा 59.18 बीघा मौजा सडा, खसरा संख्या 318 रकबा 99.02 बीघा माजा हरनिगर व खसरा संख्या 519 रकबा 51.05 बीघा मौजा सडा में खेत खसरा में प्रार्थनी के हक हिस्से में वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें एवं बेचान आदि न करे तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। खर्चा हर्जा प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अपना अपना स्वयं वहन करें।



आदेश आज दिनांक 20.10.2015 करे खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नाथूसिंह राठौड़
20/10/15
(नाथूसिंह राठौड़)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) जुद्धमालानी